[2012] 9 एस.सी.आर. 805

श्री श्याम एजेंसी

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 7589/2012)

18 अक्टूबर 2012

[के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे.जे.]

रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987:

धाराएँ 13(1) और 16 - दावा याचिका - पार्टियों की दलील- खेप "स्वयं" आधार के तहत बुक की गई - एक तिहाई तक पहुंचाई गई बिना अधिकार वाली पार्टी - परेषक द्वारा दावा याचिका रेलवे गैर-डिलीवरी के लिए माल के मूल्य का दावा कर रहा है - एक होने का दावा करने वाले अपीलकर्ता द्वारा पक्षकार बनाये जाने के लिए आवेदन इच्छुक पक्ष - तीन अन्य को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन व्यक्ति - माना गया: दावा याचिका में ट्रिब्यूनल को क्या करना है रेलवे के विरुद्ध दावे की जांच करें और निर्धारित करें प्रशासन अपने दायित्वों के निर्वहन में अपनी गलती के लिए रेलवे अधिनियम, नियमों और विनियमों के तहत नहीं दावेदारों और तीसरे पक्षों के बीच परस्पर विवाद - जिसे खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है पक्षकार बनाने के लिए आवेदन और उच्च न्यायालय सही है आदेश की पुष्टि की - रेलवे दावा न्यायाधिकरण

अधिनियम, 1987 - एस.एस.16, 18 - रेलवे अधिनियम, 1989 - एस.एस. 65 और 7 4 - रेलवे (तरीका) खेप की डिलीवरी और बिक्री से प्राप्त आय की रेलवे रसीद का अभाव), नियम, 1990 - रेलवे दावे ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियम, 1989।

दावेदार-प्रतिवादी नं. 3, एक कंपनी जिसके पास है चेन्नई स्थित प्रधान कार्यालय के व्यवसाय में लगा हुआ था सफेद क्रिस्टल चीनी का निर्माण और बिक्री। यह था दावेदार का मामला जिसे एक डीलर, अर्थात् 'एसएके' ने रखा है मुफ़्त बिक्री चीनी की खरीद के लिए दावेदार के साथ एक आदेश भुगतान की शर्तों के साथ यह निर्धारित किया गया है कि इसका समर्थन किया गया है रेलवे रसीदें संपूर्ण प्राप्त होने पर जारी की जाएंगी बिक्री पर विचार; जिसे दावेदार ने बुक किया था 1.2.201 O से परिवहन के लिए खेप कुंभकोणम से फतुहा, बिहार और वह रेलवे रसीदें "स्वयं" के रूप में निकाली गई थीं और अभिरक्षा में थीं दावेदार की और क्रेता से अपेक्षा की गई थी बिक्री मूल्य जमा करें और रेलवे रसीदों का पृष्ठांकन करवाएं इसके पक्ष में. माल गंतव्य तक पहुंच गया 10.2.1010. क्रेता बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहा और जैसा कि अपीलकर्ता ने बताया, सामान रेलवे में रखा हुआ था घाट शुल्क व्यय करने वाला गोदाम; कि दावेदार ने वरिष्ठ डीजीएम/दक्षिणी रेलवे/त्रिची को एक पत्र भेजा 23.4.2010 को और सूचित किया गया कि रेलवे प्राप्तियाँ थीं दावेदार की हिरासत में और या तो अनुरोध किया खेप को अन्य गंतव्य पर

स्थानांतरित करें या वापस लाएं कुंभकोणम को. हालाँकि, दावेदार को सूचित किया गया था रेलवे द्वारा 4.5.2010 को वह खेप भेजी गई थी 0 के बल पर 10.2.2010 को फतुहा में पहुंचाया गया क्षतिपूर्ति नोट उस व्यक्ति का खुलासा किए बिना किसे दिया गया है इसे वितरित किया गया। दावेदार-प्रतिवादी नं. 3 एक दायर किया 2010 के OA नंबर (1) 2 वाली दावा याचिका, के विरुद्ध दक्षिणी और पूर्वी मध्य रेलवे से पहले ई रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने कहा कि चूंकि खेपों को "स्वयं" आधार के तहत बुक किया गया था किसी तीसरे पक्ष को डिलीवरी बिना अधिकार के थी और राशि को लापरवाही, दुराचार और दुरूपयोग और, इसलिए, रेलवे प्रशासन मुआवज़ा देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी था गैर-डिलीवरी के लिए माल का मूल्य होना।

दावा याचिका में अपीलकर्ता ने आई.ए. दायर किया। 3/2011 के लिए हस्तक्षेप का दावा है कि यह एक इच्छुक पार्टी थी और के उचित निर्णय के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक थी दावा। एल.ए.4/2011 को प्रतिवादी संख्या द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। 2,मध्य रेलवे, तीन अन्य पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए यह तर्क देते हुए कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण के पास नहीं था इसमें मामले को आगे बढ़ाने का क्षेत्राधिकार शामिल है संविदात्मक विवाद, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और उक्त पक्षों द्वारा दायर एक शिकायत लंबित थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष. न्यायाधिकरण ने दोनों आवेदनों को आपस में जोड़ते हुए खारिज कर दिया

निजी पक्षों के बीच विवादों का निर्णय नहीं किया जा सका एक दावा याचिका में न्यायाधिकरण. पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर की गईं अपीलकर्ता द्वारा और रेलवे द्वारा बर्खास्त कर दिया गया उच्च न्यायालय।

त्वरित अपील में विचार हेतु प्रश्न न्यायालय के समक्ष यह था: क्या अपीलकर्ता कानूनी रूप से था प्रतिवादी द्वारा दायर दावा याचिका में हस्तक्षेप करने का हकदार है नहीं। रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 के तहत 3।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए:

अभिनिर्धारित किया:- 1.1 प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि दावा न्यायाधिकरण की स्थापना न्यायाधिकरण 0 के अंतर्गत की गई है। दावों की जांच और निर्धारण के लिए अधिनियम, 1987 हानि, विनाश, के लिए रेलवे प्रशासन के विरुद्ध जानवरों की क्षति, गिरावट या गैर-डिलीवरी या इसे सौंपा गया सामान रेलवे द्वारा ले जाने के लिए है, न कि इसके लिए किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध किसी दावे या विवाद का निर्णय। धारा 13 क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और निर्धारित करती है। दावा न्यायाधिकरण का अधिकार. धारा 16 का प्रावधान है दावा न्यायाधिकरण में आवेदन किया जाना है एसबी-एस (1) और उप- में उल्लिखित मामलों का सम्मान धारा 13 की धारा(1ए)। धारा 18 प्रक्रिया निर्धारित करती है और दावा न्यायाधिकरण की इस संबंध में शक्तियां। एक जोड़ पर अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ना, यह तत्व है-

कि दावे पर फैसला देने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है रेलवे के खिलाफ बनाया गया, न कि किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ। ऐसा देखा गया है कि दावा याचिका अनुबंध पर आधारित है गाड़ी दावेदार और के बीच में प्रवेश कर गई रेलवे। ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न है क्या रेलवे प्रशासन को कोई नुकसान हुआ है? का विनाश, क्षति, गिरावट या गैर-वितरण रेलवे द्वारा ले जाए जाने के लिए उसे सौंपे गए जानवर या सामान या किराए या माल ढुलाई की वापसी या मुआवजे के लिए रेलवे दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्रियों की मृत्यु या चोट दुर्घटनाएँ या अप्रिय घटनाएँ आदि [पैरा 10-12] [812-ई- जी-एच; 813-ए-8; 814-8-सी-एफ; 816-ए-डी]

1.2 रेलवे का नियम 5 (वितरण का तरीका) खेप और बिक्री से प्राप्त आय के अभाव में रेलवे रसीद), नियम, 1990 वितरण से संबंधित है नाशवान वस्तुएं ~ जब रेलवे रसीद नहीं है आगामी. उप-आर. नियम 3 के (2) में विशेष रूप से कहा गया है कि, जब रेलवे रसीद नहीं आ रही हो और खेप "स्वयं" को संबोधित है, वितरण नहीं किया जाएगा जब तक क्षतिपूर्ति नोट फॉर्म 1-ए में विधिवत निष्पादित न हो जाए और 1-8 डिलीवरी का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं प्रेषण। अपीलकर्ता या रेलवे प्रशासन के पास कंसाइनी के पास कोई मामला नहीं है माल पर दावा करने के लिए रेलवे रसीद प्रस्तुत की। पर दूसरी ओर, यह का विशिष्ट रुख रहा है रेल प्रशासन ने बताया कि यह खेप थी 10.2.2010 को फतुहा में एक तीसरे पक्ष को वितरित किया गया "क्षतिपूर्ति नोट" की

ताकत और के उत्पादन पर नहीं "रेलवे रसीद"। [पैरा 15-16] [819-8-डी-एच; 820-ए; 821-सी]

1.4 रेलवे अधिनियम, 1989 को पढ़ने पर, ट्रिब्यूनल अधिनियम के साथ-साथ 1990 के नियम और वैधानिक रूपों, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि क्या ट्रिब्यूनल को दावे की जांच और निर्धारण करना होगा रेलवे प्रशासन के खिलाफ यानी कि क्या इसके निर्वहन में रेल प्रशासन की गलती है रेलवे अधिनियम, नियम और के तहत जिम्मेदारियां विनियम और न कि आपसी विवाद दावेदार और तीसरे पक्ष। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और मामले की परिस्थितियों के अनुसार, दृश्य में कोई त्रुटि नहीं है ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया, जिसकी सही पुष्टि की गई है उच्च न्यायालय. [बराबर:ए 18-19] [825-8-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7589/2012

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर.पी. (पीडी) संख्या 1713/2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.09.2011 से उत्पन्न।

सौरव अग्रवाल, विपुल शारदा, गौरव अग्रवाल, अपीलकर्ता की और से।

सीए, सुंदरम, प्रवीण एच. पारेख, हरीश चंद्र, शशांक कुमार, जफर लेनायत, ई.आर. कुमार, विशाल प्रसाद, एकांश मिश्रा, योगेश, क्षत्रशाल राज

(पारेख एंड कंपनी के लिए), शालिनी कुमार, श्रीकांत एन. टेरडाल, पी.एस. परमार, आलोक कुमार, शकीन परमार, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

के.एस. राधाकृष्णन, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. इस अपील में हम इस प्रश्न से चिंतित हैं क्या अपीलकर्ता कानूनी रूप से हस्तक्षेप करने का हकदार है? धारा के तहत तीसरे प्रतिवादी द्वारा दायर दावा याचिका रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 का 16 (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण कार्य')।

3. 2010 की दावा याचिका ओए नंबर (1) 2 को प्राथमिकता दी गई थी दक्षिणी और पूर्वी के विरुद्ध तीसरे प्रतिवादी द्वारा रेलवे दावा न्यायाधिकरण, चेन्नई के समक्ष मध्य रेलवे बेंच ने कुल मिलाकर 9,46,85,726/- रुपये की राशि का दावा किया याचिका दायर करने की तारीख से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भुगतान की तारीख तक और अन्य परिणामी राहतों के लिए भी।

4. दावा याचिका में, अपीलकर्ता ने आई.ए. दायर किया। 3/2011 एक इच्छुक पक्ष होने का दावा करते हुए हस्तक्षेप के लिए दावे के उचित निर्णय के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। I.A.4/2011 को यहां दूसरे प्रतिवादी द्वारा भी प्राथमिकता दी गई थी मध्य रेलवे तीन अन्य पक्षों, अर्थात् सुभम को पक्षकार बनाएगा चीनी एजेंसियां, उमेश चौधरी, एक्स.

माल पर्यवेक्षक, ततुहा और अंबिका शुगर्स लिमिटेड ने तर्क दिया कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है मामले को आगे बढ़ाएँ क्योंकि इसमें संविदा संबंधी विवाद शामिल थे, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और वह द्वारा दायर की गई शिकायत उपरोक्त उल्लिखित पक्ष मुख्य न्यायिक के समक्ष लंबित हैं मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर, बिहार।

5. ट्रिब्यूनल ने दोनों आवेदनों यानी I.A.3/2011 पर सुनवाई की बी और आई .ए.4/2011 और एक सामान्य आदेश 15.4.2011 को पारित किया गया था, यह कहते हुए कि निजी पक्षों के बीच परस्पर विवाद नहीं हो सकते एक दावा याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया। यह नजारा भी लिया कि रेल प्रशासन उन पार्टियों के माध्यम से प्रयास कर रहा है कार्यवाही में देरी करना और, किसी भी परिस्थिति में, अन्य तीन पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया जा सकता है मनोरंजन किया. I.A.3/2011 और I.A.4/2011 दोनों तदनुसार थे। बर्खास्त.

6. ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर सी.आर.पी. (पीडी) संख्या 1713/2011 को यहां अपीलकर्ता द्वारा प्राथमिकता दी गई थी, 2011 की सीआरपी (पीडी) संख्या 2152 और 2011 की सीआरपी (पीडी) संख्या 2153 दक्षिणी रेलवे और मध्य रेलवे द्वारा, हाई से पहले मद्रास में न्यायिक न्यायालय। तीनों सिविल रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई हुई और एक सामान्य आदेश पारित किया गया 9.9.2011 सभी पुनरीक्षण याचिकाओं को

खारिज करते हुए पुष्टि की ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने सी.आर.पी. (पीडी) संख्या 1713/2011 इस न्यायालय के समक्ष आया है वर्तमान अपील के साथ. हालाँकि रेलवे प्रशासन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को स्वीकार कर लिया गया है उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय द्वारा पुष्टि की गई।

7. इस अपील के निस्तारण हेतु कुछ तथ्यों का सन्दर्भ है ज़रूरी। दावेदार, यहां तीसरा प्रतिवादी एक कंपनी है इसका मुख्य कार्यालय चेन्नई में है और यह व्यवसाय में लगा हुआ है सफेद क्रिस्टल चीनी के निर्माता की अपनी फैक्ट्रियाँ हैं थिरुमंथनकुडी गांव, पापियासम तालुक, तंजावुर जिला जी और ए. चित्तूर गांव, विरुधाचलम तालुक, कुड्डालोर जिला। वे उत्तरी भारतीय बाज़ारों में मुफ़्त चीनी बेचते थे परिवहन द्वारा पश्चिम बंगाल, बिहार आदि शामिल हैं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से रैक में खेप रेलवे। रेलवे की रसीदें दिखाकर बनाई जाती हैं परेषिती को "स्वयं" के रूप में दर्शाया जाता है जिसे उसके बाद पृष्ठांकित किया जाता है बिक्री मूल्य के भुगतान पर क्रेता को प्रेषक। पृष्ठांकित परेषिती/खरीदार माल की डिलीवरी लेता है रेलवे रसीदों के समर्पण द्वारा संबंधित गंतव्य। दावेदार का कहना है कि एक डीलर, जिसका नाम शुभम शुगर है एजेंसियों, कोलकाता ने दावेदार को एक ऑर्डर दिया भुगतान के साथ 27000 क्विंटल निःशुल्क बिक्री चीनी की खरीद शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि समर्थित रेलवे रसीदें होंगी संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। दावेदार ने

कहा कि उसने 1.2.2010 को खेप बुक की है कुंभकोणम से फतुहा, बिहार तक परिवहन और वह रेलवे रसीदें "स्वयं" के रूप में निकाली गई थीं और हिरासत में थीं दावे का विवरण और क्रेता से भुगतान की अपेक्षा की गई थी बिक्री मूल्य और रेलवे रसीदें उसमें पृष्ठांकित करवाएं कृपादृष्टि। माल 10.2.1010 को गंतव्य पर पहुंच गया। जैसा कि कहा गया है, खरीदार बिक्री मूल्य और सामान का भुगतान करने में विफल रहा अपीलकर्ता को रेलवे गोदाम में रखा गया था घाटशुल्क शुल्क. इसके अलावा, यह कहा गया कि दावेदार तब सीनियर डीजीएम/दक्षिणी रेलवे/त्रिची को एक पत्र भेजा 23.4.2010 और सूचित किया कि रेलवे रसीदें थीं दावेदार की हिरासत और या तो स्थानांतरित करने का अनुरोध किया खेप को अन्य गंतव्य तक ले जाना या वापस लाना कुम्भकोणम. हालाँकि, दावेदार को सूचित कर दिया गया था रेलवे द्वारा 4.5.2010 को माल वितरित किया गया क्षतिपूर्ति नोट के आधार पर 10.2.2010 को फतुहा में उस व्यक्ति का खुलासा किए बिना· जिसे यह वितरित किया गया था। दावेदार ने यह रुख बनाए रखा कि खेप के बाद से "स्वयं' आधार के तहत बुक किया गया था, किसी तीसरे पक्ष को डिलीवरी अधिकार विहीन था और लापरवाही, कदाचार के समान था और दुरूपयोग और इसलिए, रेलवे प्रशासन का मूल्य होने के कारण मुआवज़ा देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है गैर-डिलीवरी के लिए माल।

8. हालाँकि, अपीलकर्ता ने यह रुख कायम रखा कि यह था दलाल शुभम के माध्यम से दावेदार से चीनी की खरीददार शुगर एजेंसियाँ, कोलकाता और वह पूरा भुगतान था जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से निर्देश पर बनाया गया चेक/आरटीजीएस आदि जिन्हें स्वीकार और पावती दी गई थी दावा करने वाला। इसके अलावा, यह भी दलील दी गई कि दावेदार के पास है पूरे तथ्य दबाये. यह कहा गया कि अपीलकर्ता के पास था बिना भुगतान के चीनी की डिलिवरी नहीं मिली और बाहर कुल 7,87,52,850/- रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका था रु. 7,30,22,052.40 और शेष राशि 57,30,797.60 रुपये की पेशकश की गई, लेकिन दावेदार ने स्वीकार नहीं किया।

9. हम, इस अपील में, मुख्य रूप से चिंतित हैं प्रश्न करें कि क्या अपीलकर्ता को स्वयं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। 2010 की दावा याचिका संख्या OA(1) संख्या 2 में पक्षकार बनाया गया ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है और क्या निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ हैं या नहीं। चूंकि दावा याचिका पहले से लंबित है. न्यायाधिकरण, हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या रेलवे प्रशासन और इसमें अपीलकर्ता दावे के लिए उचित और आवश्यक पक्ष हैं डी याचिका पर फैसला होना है.

10. न्यायाधिकरण के अंतर्गत न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है अधिनियम, 1987. इसकी प्रस्तावना का संदर्भ इंगित करेगा इसके निर्माण का उद्देश्य और वस्तु। न्यायाधिकरण की प्रस्तावना अधिनियम, 1987 इस प्रकार है:

> "रेलवे की स्थापना के लिए एक अधिनियम दावों की जांच और निर्धारण के लिए दावा न्यायाधिकरण हानि, विनाश, के लिए रेलवे प्रशासन के विरुद्ध जानवरों या सामान की क्षति, ख़राबी या गैर-डिलीवरी. इसे रेलवे द्वारा ले जाने या वापसी के लिए सौंपा गया है किराया या माल ढुलाई या मृत्यु या चोट के लिए मुआवजे के लिए रेलवे दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले यात्रियों या अप्रिय घटनाएँ और उससे जुड़े मामलों के लिए या उसके लिए आकस्मिक।"

प्रस्तावना से स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण रहा है दावों की जांच करने और उनका निर्धारण करने के लिए स्थापित किया गया हानि, विनाश, के लिए रेलवे प्रशासन के विरुद्ध जानवरों या सामान की क्षति, ख़राबी या गैर-डिलीवरी इसे रेलवे द्वारा ले जाने के लिए सौंपा गया है, न कि न्यायनिर्णयन के लिए किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध किसी दावे या विवाद का।

11. ट्रिब्यूनल अधिनियम का अध्याय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, दावा न्यायाधिकरण की शक्तियाँ और अधिकार। की धारा 13 ट्रिब्यूनल अधिनियम इस प्रकार पढ़ता है:

"13. **अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और अधिकार दावा न्यायाधिकरण.-**(1) दावा न्यायाधिकरण कार्य करेगा, नियत दिन से ही, ऐसे सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्राधिकार जैसा कि उससे ठीक पहले प्रयोग किया जा सकता था। किसी भी सिविल न्यायालय या दावा आयुक्त द्वारा दिन रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त,-

(ए) रेलवे की जिम्मेदारी से संबंधित के अध्याय VII के अंतर्गत वाहक के रूप में प्रशासन दावों के संबंध में रेलवे अधिनियम-

(i) हानि, विनाश, क्षति के लिए मुआवजा, पशुओं का खराब होना या न आना या रेलवे प्रशासन को सौंपा गया माल रेलवे द्वारा परिवहन के लिए;

(ii) धारा 82 ए के तहत देय मुआवजा रेलवे अधिनियम या बनाये गये नियम उसके तहत; और

(बी) किराए या आंशिक वापसी के दावों के संबंध में उसके संबंध में भुगतान किए गए किसी भी भाड़े की वापसी के

लिए रेलवे प्रशासन को सौंपे गए जानवर या सामान रेलवे द्वारा ले जाया जाएगा।

(1ए) दावा न्यायाधिकरण आगे भी कार्रवाई करेगा अनुभाग के प्रावधानों के प्रारंभ होने की तिथि रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 124ए, ऐसे सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्राधिकार प्रयोग योग्य थे उस तिथि से ठीक पहले किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा संबंध में अब रेलवे द्वारा देय मुआवजे के दावे उक्त अधिनियम की धारा 124ए के तहत प्रशासन या उसके तहत बनाए गए नियम।

(2) रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) के प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम, जहां तक संभव हो, बने रहेंगे किसी भी दावे की जांच करने या उसका निर्धारण करने के लिए लागू इस अधिनियम के तहत दावा न्यायाधिकरण द्वारा।"

ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 16 आवेदन से संबंधित है दावा न्यायाधिकरण और इस प्रकार पढ़ता है:

"16. दावा न्यायाधिकरण को आवेदन.- (1) चाहने वाला व्यक्ति उप-में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कोई राहत

धारा 13 की धारा (1) या उपधारा (1 ए) बनाई जा सकती है दावा न्यायाधिकरण के लिए एक आवेदन।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन इस प्रकार होगा प्रपत्र और ऐसे दस्तावेज़ या अन्य के साथ होना चाहिए इसे दाखिल करने के संबंध में साक्ष्य और ऐसी फीस द्वारा आवेदन और सेवा के लिए ऐसी अन्य फीस द्वारा या निर्धारित प्रक्रियाओं का निष्पादन:

बशर्ते कि इस संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा उप-खंड (ए) के उप-खंड (ii) के तहत एक आवेदन का धारा (1) या, जैसा भी मामला हो, की उपधारा (1ए)। धारा 13।"

ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 18 प्रक्रिया से संबंधित है दावा न्यायाधिकरण की शक्तियां और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"18. दावा न्यायाधिकरण की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ.- (1) दावा न्यायाधिकरण इसके लिए बाध्य नहीं होगा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (1908 का 5), लेकिन प्रकृति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा न्याय और, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन और किसी भी नियम के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण के पास

शक्तियां होंगी स्थानों के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करें और इसकी पूछताछ का समय।

(2) दावा न्यायाधिकरण प्रत्येक आवेदन पर निर्णय करेगा यथासंभव शीघ्रता से और सामान्यतः प्रत्येक आवेदन पर लिखित दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा अभ्यावेदन और शपथ पत्र और ऐसी मौखिक सुनवाई के बाद तर्क जो आगे बढ़ाए जा सकते हैं।

(3) दावा न्यायाधिकरण के प्रयोजनों के लिए होगा इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, वही शक्ति जैसा कि नागरिक संहिता के तहत सिविल न्यायालय में निहित है प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5), एक मुकदमे की सुनवाई करते समय, सम्मान में निम्नलिखित मामलों में से, अर्थात्:

(ए) किसी को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना व्यक्ति और शपथ पर उसकी जांच करना;

(बी) की खोज और उत्पादन की आवश्यकता है दस्तावेज़;

(सी) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(डी) धारा 123 और 124 के प्रावधानों के अधीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ की मांग करना या किसी भी कार्यालय से ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज़ की प्रति;

(ई) की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना गवाह या दस्तावेज़;

(च) अपने निर्णयों की समीक्षा करना;

(छ) किसी आवेदन को डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज करना या उस पर निर्णय लेना पक्षपातवाला;

(ज) किसी की भी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करना डिफ़ॉल्ट के लिए आवेदन या उसके द्वारा पारित कोई आदेश पा आरटीई;

(i) कोई अन्य सामग्री जो निर्धारित की जा सकती है।"

रेलवे दावा न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमों का नियम 44 1989 ट्रिब्यूनल को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करता है न्याय का। उपर्युक्त के संयुक्त वाचन पर प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है रेलवे के खिलाफ किए गए दावे का फैसला करें, न कि उसके खिलाफ एक तीसरी पार्टी। दावा याचिका, यह

देखा गया है, पर आधारित है दावेदार और के बीच हुआ गाड़ी का अनुबंध रेलवे।

12. ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या रेल प्रशासन ने कोई हानि, विनाश, जानवरों या सामान की क्षति, ख़राबी या गैर-डिलीवरी इसे रेलवे द्वारा ले जाने या किराए की वापसी के लिए सौंपा गया है माल ढुलाई या यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजे के लिए रेल दुर्घटनाओं या अप्रिय घटनाओं आदि के परिणामस्वरूप। अधिनियम का अध्याय III क्षेत्राधिकार, शक्तियों और से संबंधित है न्यायाधिकरण का अधिकार।

13. ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 13(1)(ए), पहले से ही संकेत दिया गया है, निर्णय लेने के लिए ट्रिब्यूनल को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करता है अध्याय के अंतर्गत वाहक के रूप में रेलवे की जिम्मेदारियाँ उपर्युक्त के संबंध में रेलवे अधिनियम, 1989 का VI । रेलवे के ख़िलाफ़ किए गए दावे. रेलवे का अध्याय IX अधिनियम, 1989 माल की ढुलाई से संबंधित है। की धारा 61 रेलवे अधिनियम, 1989 कहता है कि प्रत्येक रेलवे प्रशासन ऐसा करेगा माल और अनुभाग की ढुलाई के लिए दर-पुस्तकें आदि बनाए रखना 62 माल की प्राप्ति आदि के लिए शर्तें लगाता है। धारा 65

इस मामले के निपटारे के उद्देश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है इसलिए यहां से निकाला गया:

"65. रेलवे रसीद। (1) एक रेलवे प्रशासन-

(ए) ऐसे मामले में जहां माल को ए द्वारा लोड किया जाना है ऐसा माल सौंपने वाला व्यक्ति, पूरा होने पर ऐसी लोडिंग; या

(बी) किसी अन्य मामले में, माल की स्वीकृति पर इसके द्वारा, ऐसे प्रारूप में रेलवे रसीद जारी करें, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा.

(2) रेलवे रसीद प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी वजन और उसमें बताए गए पैकेजों की संख्या:

बशर्ते कि वैगन में खेप के मामले में- भार या ट्रेन-भार और वजन या संख्या अधिकृत रेलवे कर्मचारी द्वारा पैकेजों की जाँच नहीं की जाती है इस संबंध में, और उस आशय का एक बयान दर्ज किया गया है ऐसी रेलवे रसीद उस पर साबित करने का भार है वजन या, जैसा भी मामला हो, पैकेजों की संख्या उसमें कहा गया है, प्रेषक, परेषिती या पर निहित होगा समर्थनकर्ता।"

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 74 पासिंग से संबंधित है रेलवे रसीद द्वारा कवर किए गए माल में संपत्ति की और वही इस प्रकार पढ़ता है:

> "74. **इसके अंतर्गत आने वाले माल में संपत्ति का हस्तांतरण रेलवे रसीद.-** खेप में शामिल संपत्ति रेलवे रसीद द्वारा कंसाइनी को भेजा जाएगा या जैसा भी मामला हो, ऐसी डिलीवरी पर पृष्ठांकन करें उसे रेलवे रसीद और उसके पास सभी अधिकार होंगे प्रेषक की देनदारियां।"

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 76 आत्मसमर्पण से संबंधित है रेलवे रसीद का विवरण इस प्रकार है:

> **"76. रेलवे रसीद का समर्पण.-** रेलवे प्रशासन एक के तहत खेप वितरित करेगा ऐसी रेलवे रसीद के समर्पण पर रेलवे रसीद:
>
> बशर्ते कि मामले में रेलवे रसीद न हो आगामी, खेप को वितरित किया जा सकता है रेलवे प्रशासन की राय में हकदार व्यक्ति माल प्राप्त करने के लिए, उस तरीके से जो संभव हो निर्धारित।"

धारा 77 रेलवे प्रशासन की शक्ति से संबंधित है कुछ मामलों में माल वितरित करना या उसकी बिक्री से प्राप्त आय इस प्रकार पढ़ता है:

> **"77. रेलवे प्रशासन की कार्यकुशलता प्रदान करने की शक्ति कुछ मामलों में माल या उसकी बिक्री से प्राप्त आय.-**जहां कोई भी रेलवे रसीद नहीं आ रही है खेप या किसी खेप की बिक्री आय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा रेलवे प्रशासन पर दावा किया गया ऐसी खेप या बिक्री की डिलीवरी रोक सकता है जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ेगा और ऐसा वितरित करेगा खेप या बिक्री आय इस तरह से हो सकती है निर्धारित।"

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 87 नियम बनाने का अधिकार देती है केंद्र सरकार पर शक्ति, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़ता है:

> **"87. मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति इस अध्याय में.-** (1) केंद्र सरकार, द्वारा अधिसूचना, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएं अध्याय.
>
> (2) विशेष रूप से, और बिना किसी पूर्वाग्रह के पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता, ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं निम्नलिखित सभी या किसी एक मामले के लिए:-

*** *** ***

*** *** ***

(इ)खेप किस प्रकार हो सकती है धारा के तहत रेलवे रसीद के बिना वितरित किया गया 76;

(एफ) खेप की डिलीवरी या बिक्री का तरीका इसके तहत हकदार व्यक्ति को प्राप्त होता है धारा 77;

*** *** ***

*** *** ***

14. केन्द्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हुई की धारा 87(2) के खंड (ई) और (एफ) द्वारा प्रदत्त रेलवे अधिनियम, 1989 सामान्य खंड की धारा 22 के साथ पठित अधिनियम, 1897 ने रेलवे (रेलवे की डिलीवरी का तरीका) तैयार किया है रेलवे की अनुपस्थिति में खेप और बिक्री आय रसीद), नियम, 1990 (संक्षेप में "1990 नियम")।

15. अपीलकर्ता या रेलवे प्रशासन के पास नं मामला यह है कि मेसर्स सुभम शुगर एजेंसीज, कलकत्ता माल भेजने वाले ने दावा करने के लिए रेलवे रसीद प्रस्तुत की थी चीज़ें। दूसरी ओर, यह विशिष्ट रुख रहा है रेलवे प्रशासन जिस पर खेप पहुंचाई गई थी 10.2.2010 को फतुहा के बल

पर किसी तीसरे पक्ष को "क्षतिपूर्ति नोट" न कि "रेलवे" के उत्पादन पर रसीद"। 1990 नियम, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, से संबंधित है खेपों की डिलीवरी और बिक्री आय का तरीका रेलवे रसीद का अभाव. के नियम 3 के उपनियम (1) और (2). 1990 के नियम हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और वही हैं यहां से निकाला गया:

"3. रेलवे द्वारा खेप की डिलीवरी रसीद नहीं आ रही है:- (1) जहां रेलवे रसीद नहीं आ रही है, खेप आ सकती है। उस व्यक्ति को दिया गया, जो रेलवे की राय में प्रशासन माल प्राप्त करने का हकदार है और कौन किसी भी क्षतिपूर्ति के निष्पादन पर उसे वही प्राप्त होगा फॉर्म । में निर्दिष्ट अनुसार नोट: प्रदान किया;

हालाँकि, यदि परेषिती एक है सरकारी अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में, ऐसी डिलीवरी बिना मुद्रांकित क्षतिपूर्ति नोट पर बनाया जा सकता है)।

(2) जहां रेलवे रसीद नहीं आ रही है और प्रेषक द्वारा खेप को स्वयं को संबोधित किया जाता है, विधिवत क्षतिपूर्ति नोट के बिना डिलीवरी नहीं की जाएगी फॉर्म I-A

और 1-8 में निष्पादित किया जाता है खेप की डिलीवरी का दावा करने वाले व्यक्ति।"

1990 के नियमों का नियम 5 खराब होने वाली वस्तुओं की डिलीवरी से संबंधित है लेख जब रेलवे रसीद नहीं आ रही है और वही इस प्रकार पढ़ता है:

"(5) नाशवान वस्तुओं की डिलीवरी जब रेलवे रसीद नहीं आ रही है:- (1) फिर भी इन नियमों में निहित कुछ भी, जहां खेप इसमें नाशवान वस्तुएँ होती हैं और रेलवे रसीद होती है नहीं आने पर ऐसी खेप पहुंचाई जा सकती है वह व्यक्ति, जो रेलवे प्रशासन की राय में है ऐसी खेप प्राप्त करने का हकदार है, और ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन डिलीवरी लेगा, अर्थात्:-

(ए) यदि रेलवे रसीद की चालान प्रति उपलब्ध है डिलीवरी लेने और बुकिंग के समय ऐसे परेषिती का नाम दिया जाए जो डिलीवरी का दावा कर रहा हो डिलीवरी लेने से पहले व्यक्ति को एक कार्यान्वित करना होगा फॉर्म । में निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति नोट; या

(बी) (i) यदि रेलवे रसीद की चालान प्रति नहीं है डिलीवरी लेते समय उपलब्ध; या

(ii) यदि ऐसी चालान प्रति उपलब्ध है और कंसाइनमेंट "स्वयं" के लिए बुक किया गया है,

ऐसे व्यक्ति को के बराबर राशि जमा करनी होगी माल ढुलाई के अलावा सुरक्षा के माध्यम से खेप की लागत और ऐसी डिलीवरी लेने से पहले अन्य शुल्क माल.

(2) यदि कोई राशि जमा की गई है उप-नियम (1) के खंड (बी) के तहत सुरक्षा, ऐसी राशि होगी प्रस्तुत करने पर रेलवे प्रशासन द्वारा वापस कर दिया जाएगा तारीख से छह महीने के भीतर मूल रेलवे रसीद ऐसी डिलीवरी लेने की।

(3) मूल रेलवे रसीद के अभाव में रिफंड प्रपत्र में क्षतिपूर्ति नोट के निष्पादन पर प्रदान किया जा सकता है । या I-A और 1-B, जैसा भी मामला हो, चालान प्रदान किया गया रेलवे रसीद की प्रति और विवरण उपलब्ध है खेप के संदर्भ में जोड़ा जा सकता है चालान प्रति, लेने की तारीख से छह महीने के भीतर वितरण।"

16. 1990 के नियम 3(1) के तहत फॉर्म I से संबंधित है "क्षतिपूर्ति नोट" कि खेप कब आनी है 'व्यक्ति' को दिया गया, 'स्वयं' को नहीं। अगर ये किसी 'व्यक्ति' को है तो उसे 'कंसाइनी' द्वारा हस्ताक्षरित एक क्षतिपूर्ति नोट प्रस्तुत करना होगा। नियम 3 के उप-नियम (2) में विशेष रूप से

कहा गया है कि, जब रेलवे रसीद नहीं आ रही है और खेप का पता चल गया है "स्वयं' को, विधिवत क्षतिपूर्ति नोट के बिना डिलीवरी नहीं की जाएगी फॉर्म I-A और 1-B में निष्पादित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं खेप की डिलीवरी का दावा करना। का प्रासंगिक भाग आसान संदर्भ के लिए फॉर्म 1-ए और 1-बी नीचे दिए गए हैं:

"फॉर्म 1-ए

[नियम 3(2) देखें]

क्षतिपूर्ति नोट का प्रपत्र

- - - रेलवे

इनडेम्निटी नोट

** मैं/हम एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं कि मैंने प्राप्त किया है_ _ _ _रेलवे ---------- मूल्य रु. -------- कौन मेरे/हमारे द्वारा भेजा गया था और स्वयं/मूल्य के रूप में बुक किया गया था का स्टेशन रेलवे---------- देय, से पर या उसके बारे में के दिन---------- के लिए रेलवे रसीद जो हो गया और ---------- मेरे लिए, मेरे उत्तराधिकारियों के लिए, निष्पादक और प्रशासक और हमारी कंपनी । फर्म के लिए, उनके नियुक्त, और उत्तराधिकारी।

** मैं/हम इस तरह की डिलीवरी पर विचार करने का वचन देते हैं धारण करने के लिए कहा गया है।

* भारत के राष्ट्रपति, उनके एजेंट और सेवक _ _ _ _ _ रेलवे प्रशासन, उसके एजेंट और नौकर उक्त सभी दावों के संबंध में हानिरहित और क्षतिपूर्ति योग्य चीज़ें।

** मैं/हम रेलवे को मांग पर भुगतान करने का भी वचन देते हैं प्रशासन माल भाड़ा शुल्क, कम शुल्क, घाट शुल्क और कोई भी अन्य आरोप जो बाद में संबंध में उचित पाए जा सकते हैं

इस लेन-देन का. और ** मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता हैं, प्रेषक के नीचे हस्ताक्षर कर रहे हैं इन वस्तुओं का प्रमाणित किया जाता है कि पहला हस्ताक्षरकर्ता वास्तविक स्वामी है माल की; और वह ** मैंने/हमने उक्त संपूर्ण कार्य किया है। प्रेषक के साथ समान रूप से दायित्व, और इस उद्देश्य के लिए ** मैं/हम इस पर मेरा/हमारा हस्ताक्षर** लगाएं।

गवाह के हस्ताक्षर..... प्रेषक के हस्ताक्षर.....

पिता का नाम..... **पिता का नाम.....

उम्र..... उम्र.....

पेशा..... पेशा.....

निवास स्थान..... निवास स्थान.....

.....

कंपनी/प्रपत्र का पदनाम एवं मुहर

.....

पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का स्थान"

गवाह के हस्ताक्षर ..... ज़मानती के हस्ताक्षर .....

पिता का नाम..... **पिता का नाम.....

आयु..... आयु.....

पेशा..... पेशा ..... "

"फॉर्म 1-ए

[नियम 3(2) देखें]

क्षतिपूर्ति नोट का प्रपत्र

- - - रेलवे

इनडेम्निटी नोट

** मैं/हम एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं कि मैंने प्राप्त किया है_ _ _ _रेलवे ---------- मूल्य रु. -------- कौन मेरे/हमारे द्वारा भेजा गया था और स्वयं/मूल्य के रूप में बुक किया गया था का स्टेशन रेलवे---------- देय, से पर या उसके बारे में के दिन---------- के लिए रेलवे रसीद जो हो गया और ---------- मेरे लिए, मेरे उत्तराधिकारियों के लिए, निष्पादक और प्रशासक और हमारी कंपनी । फर्म के लिए, उनके नियुक्त, और उत्तराधिकारी।

** मैं/हम इस तरह की डिलीवरी पर विचार करने का वचन देते हैं धारण करने के लिए कहा गया है।

* भारत के राष्ट्रपति, उनके एजेंट और सेवक _ _ _ _ _ रेलवे प्रशासन, उसके एजेंट और नौकर उक्त सभी दावों के संबंध में हानिरहित और क्षतिपूर्ति योग्य चीज़ें।** मैं/हम रेलवे को मांग पर भुगतान करने का भी वचन देते हैं प्रशासन माल भाड़ा शुल्क, कम शुल्क, घाट शुल्क और कोई

भी अन्य आरोप जो बाद में संबंध में उचित पाए जा सकते हैं

इस लेन-देन का. और ** मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता हैं, प्रेषक के नीचे हस्ताक्षर कर रहे हैं इन वस्तुओं का प्रमाणित किया जाता है कि पहला हस्ताक्षरकर्ता वास्तविक स्वामी है माल की; और वह ** मैंने/हमने उक्त संपूर्ण कार्य किया है। प्रेषक के साथ समान रूप से दायित्व, और इस उद्देश्य के लिए ** मैं/हम इस पर मेरा/हमारा हस्ताक्षर** लगाएं।

गवाह के हस्ताक्षर..... प्रेषक के हस्ताक्षर.....

पिता का नाम..... **पिता का नाम.....

उम्र..... उम्र.....

पेशा..... पेशा.....

निवास स्थान..... निवास स्थान.....

.....

कंपनी/प्रपत्र का पदनाम एवं मुहर

.....

पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का स्थान"

गवाह के हस्ताक्षर ..... ज़मानती के हस्ताक्षर .....

पिता का नाम..... **पिता का नाम.....

आयु..... आयु.....

पेशा..... पेशा ..... "

17. फॉर्म 1-ए, क्षतिपूर्ति नोट में, प्रेषक को हस्ताक्षर करना होगा यह प्रमाणित करते हुए कि वह माल का वास्तविक मालिक है। फॉर्म 1-8, क्षतिपूर्ति नोट पर प्रेषक को अधिकृत करने वाले द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए डिलीवरी लेने वाला व्यक्ति. मुद्रांकित क्षतिपूर्ति की प्रति नोट को प्रेषक द्वारा निष्पादित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए अग्रेषण स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा. दूसरे शब्दों में, फॉर्म 1-ए और फॉर्म 1-8 के तहत निर्धारित सभी औपचारिकताएं का अनुपालन करना होगा, जब रेलवे रसीद नहीं है आगामी और खेप को प्रेषक द्वारा संबोधित किया जाता है आत्म के लिए। रेलवे तब तक डिलीवरी को प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि वे न हों औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

18. रेलवे अधिनियम, 1989, ट्रिब्यूनल को पढ़ने पर अधिनियम के साथ-साथ 1990 के नियम और वैधानिक प्रपत्र, हम हैं सुविचारित दृष्टिकोण से कि ट्रिब्यूनल को क्या जांच करनी है और रेलवे प्रशासन के विरुद्ध दावा निर्धारित करें, वह यह कि क्या इसमें रेलवे प्रशासन की गलती है रेलवे अधिनियम, नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना और विनियमों के बीच परस्पर विवाद नहीं दावेदार और तीसरे पक्ष।

19. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले में, हमें ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मिली, जो· उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। नतीजतन, अपील है बर्खास्त.

हालाँकि, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम नहीं हैं मामले की खूबियों और उसी पर अपनी राय व्यक्त करना न्यायाधिकरण द्वारा कानून के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

आर.पी.

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऐश्वर्या एस. अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****